



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 150]
No. 150]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 30, 1984/चैत्र 10, 1906
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 30, 1984/CHAITRA 10, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
आदेश
नई दिल्ली, 30 मार्च, 1984

का. आ. 227(अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./83 :—केंद्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.आ. 318(अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./76 तारीख 27 अप्रैल, 1976 द्वारा (जिसे इसमें पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), मैसर्स प्लाईवोर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पाम्पोर, जम्मू कश्मीर नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध 26 अप्रैल, 1981 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को प्राधिकृत किया था ;

और, केंद्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि लोक-हित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहे 31 मार्च, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए ऐसे बने रहने के लिए समय-समय पर निदेश जारी किए थे (देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास

विभाग) के आदेश सं. का.आ. 318(अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./81, तारीख 25 अप्रैल, 1981, का.आ. 287(अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./82, तारीख 26 अप्रैल, 1982, का.आ. 763(अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./82, तारीख 25 अक्टूबर, 1982 का. आ. सं. 233(अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./83 तारीख 28 मार्च, 1983 और का.आ. 605(अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./83, तारीख 29 सितम्बर, 1983) ।

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि लोकोहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 30 जून, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 05) की धारा 18क की उप-धारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 30 जून, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 2(6)/81-सी.यू.एस.]

ए. पी. मखन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 30th March, 1984

S.O. No. 227(E)|18AA|IDRA|84.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 319(E)|18AA|IDRA|76, dated the 27th April, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Jammu and Kashmir Industries Limited to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Flyboard Industries Limited, Pampore, Jammu and Kashmir, for a period of five years, that is, upto and inclusive of the 26th April, 1981;

And, whereas, the Central Government being of the opinion that it is expedient in public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of five years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1984 (vide Orders of

the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 318(E)|18AA|IDRA|81, dated the 25th April, 1981, S.O. 287(E)|18AA|IDRA|82, dated the 26th April, 1982, S.O. 763(E)|18AA|IDRA|82, dated the 25th October, 1982, S.O. 233(E)|18AA|IDRA|83, dated the 28th March, 1983 and S.O. 695(E)|18AA|IDRA|83, dated the 29th September, 1983);

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 30th June, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 30th June, 1984.

[File No. 2(6)|81-CUS.]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.